

लखनऊ : 4 फरवरी 2023

Lucknow: एसएमएस लखनऊ द्वारा प्रिंसिपल कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन







एसएमएस लखनऊ द्वारा प्रिंसिपल कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन

4 फरवरी, 2023 को स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, लखनऊ में 'प्रिंसिपल कॉन्क्लेव 2023 – चैलेंजेज इन इम्प्लीमेंटेशन' का आयोजन किया गया। श्री भगवती सिंह, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ मुख्य अतिथि तथा डॉ. मनोरमा सिंह, इग्रू लखनऊ की क्षेत्रीय निदेशक एवं हैप्पीनेस पाठ्यचर्या बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य प्रभारी डॉ. सौरभ मालवीय मुख्य वक्ता थे।

एसएमएस लखनऊ के सचिव तथा मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्री शरद सिंह, निदेशक प्रो. (डॉ.) मनोज मेहरोत्रा, महानिदेशक- तकनीकी प्रो. (डॉ.) भरत राज सिंह, के साथ एसोसिएट डायरेक्टर- प्रो. (डॉ.) धर्मेंद्र सिंह, एसएमएस लखनऊ ने भाग लिया। कॉन्क्लेव में लखनऊ और आसपास के जिलों के विभिन्न स्कूल/कॉलेजों तथा एसएमएस लखनऊ के फैकल्टी सहित सौ से अधिक प्राचार्यों ने भाग लिया।

कान्क्लेव में चर्चा हुई कि नीति सही समय पर आई है और इसका उद्देश्य बहुत ही नेक है। लेकिन कागज पर नीति बनाने और उसका पालन करने में जमीन-आसमान का अंतर है। एनईपी 2020 की सफलता और इसके कार्यान्वयन की गति काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार, विश्वविद्यालय और स्कूल इसके सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों से कितनी सफलतापूर्वक निपट सकते हैं।

एनईपी 2020 की चर्चा में यह बात सामने आई है कि इसमें लचीलापन है, इसलिए शिक्षार्थी अपने सीखने के तरीके चुन सकते हैं; कला, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों को समान रूप से बढ़ावा देना ताकि शिक्षार्थी अपनी रुचि के अनुसार कुछ भी चुन सकें; बहु-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण (विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल में); रटने की बजाय अवधारणात्मक शिक्षा पर जोर; रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच; सहयोग, टीमवर्क, सहानुभूति, लचीलापन जैसे जीवन कौशल विकसित करना; सीखने के लिए मौजूदा योगात्मक मूल्यांकन के बजाय नियमित रचनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

मूलभूत चरणों से, युवा छात्रों को कई भाषाओं से अवगत कराया जाएगा क्योंकि बहुभाषावाद के महान संज्ञानात्मक लाभ हैं और जीवन के शुरुआती वर्षों में बच्चे बहुत जल्दी भाषाओं को ग्रहण कर लेते हैं। भारत की समृद्ध, शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए, छात्रों के लिए आवश्यक, समृद्ध विकल्प के रूप में स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर संस्कृत की पेशकश की जाएगी। जबिक तिमल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया जैसी भाषाओं को संभवतः उन लोगों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल के रूप में पेश किया जाएगा जो उनका अध्ययन करने में रुचि रखते हैं।

नीति उच्च शिक्षा स्तर पर क्रांतिकारी संरचनात्मक सुधारों को पेश करना चाहती है। यह स्नातक स्तर पर एक लचीले तीन या चार साल के डिग्री प्रोग्राम स्ट्रक्चर को बढ़ावा देता है, जिससे शिक्षार्थियों के लिए कई एग्जिट पॉइंट की अनुमति मिलती है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और होलिस्टिक हेल्थ जैसे समकालीन विषयों को बढ़ावा देने के लिए भी एक ठोस प्रयास किया जाएगा, जिन्हें कल के करियर विकल्पों के रूप में जाना जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कॉलेज शिक्षा के लिए नियामक निकाय के रूप में भारत के उच्च शिक्षा आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का अनुमान है।
